09 कल के नागरिक निर्मित करना : सारे संसार में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का संक्षिप्त सर्वेक्षण

ऐन हॉर्विटज़

सामाजिक विज्ञान की शिक्षा को समझना और उसको बढ़ावा देना सरल मामला नहीं है। ये विषय – इतिहास, समाज शास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान – अपनी परिभाषा के अनुसार ''ठोस'' विज्ञान नहीं हैं। किसी विद्यार्थी को इनमें महारथ हासिल करने के लिए ऐसे ढंग से जानकारी की व्याख्या करने और समीक्षात्मक दृष्टि से सोचने में समर्थ होना जरूरी है। ऐसा उन विद्यार्थियों से अपेक्षित नहीं है जो बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान और साक्षरता हासिल कर रहे हैं। आखिरकार, a2 + b2=c2 ही होगा चाहे आप जकार्ता में हों या नैरोबी या पेरिस में। एक सेब तो सेब ही रहेगा भले ही आप किसी भी महाद्वीप में हों। परन्तु, उपनिवेशवाद की विरासत, पूँजीवाद के फायदे और नुकसान, या समाज में स्त्रियों का उचित स्थान, इनके बारे में निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया विभिन्न देशों में, और किसी देश की सीमाओं के भीतर भी, बहुत भिन्न हो सकती है।

शायद इसी ''लचीलेपन'' के कारण, पिछले कुछ दशकों में अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय में नीति बनाते समय और प्रगति का मूल्यांकन करते समय सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा पढ़ने, लिखने और अंकगणित पर अधिक जोर देने की प्रवृत्ति रही है। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक मूल्यांकन, ''ट्रैन्ड इन इन्टरनेशनल मैथेमैटिक्स एण्ड साइंस स्टडी (टीआईएमएसएस)'' और ''प्रोग्रैस इन इन्टरनेशनल रीडिंग लिटरेसी स्टडी (पीआईआरएलएस)'', सामाजिक विज्ञान सामग्री में विद्यार्थियों की उपलब्धि को नहीं नापते। एक अन्य जानामाना मूल्यांकन ''प्रोग्राम फॉर इन्टरनैशनल स्टूडेंट एसैसमेन्ट (पीआईएसए)'' भी पढ़ने, गणित और विज्ञान पर केन्द्रित रहता है। हालाँकि यह जरूर है कि समस्या सुलझाने की क्षमता को नापने के लिए इसमें एक छोटा अन्तर–सांस्कृतिक भाग भी होता है। पीआईएसए केवल 65 देशों में उपयोग किया जाता है, और इसके सबसे हाल के दौर में भाग लेने वालों में अफ्रीका के उप–सहारा क्षेत्र का कोई देश शामिल नहीं था।

एक वैश्विक मूल्यांकन, ''इन्टरनेशनल ऐसोसिएशन फॉर द इवैल्युएशन ऑफ ऐजुकेशनल एचीवमेंट (आईईए) सिविक ऐजुकेशन स्टडी'' जरूर विद्यार्थियों की इतिहास तथा भूगोल की समझ और नागरिक योग्यताओं को मापता है, लेकिन 2009 में इसके अन्तिम दौर में केवल 39 देशों ने भाग लिया। पुनः, भाग लेने वाले देशों की सूची में विविधता का अभाव था; इनमें 64% यूरोपियन, 15% लैटिन अमेरिकन, 13% एशियन थे, और शेष प्रतिशत में एक भी अफ्रीकी देश का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के शिक्षा विभाग ने अपने एक निर्णय, जो सामाजिक विज्ञान के ऊपर गणित, विज्ञान और पढ़ने की प्रमुखता को प्रतिबिम्बित करता हुआ माना जा सकता है, में अमेरिका को आईईए सिविक ऐजुकेशन स्टडी के 2009 के दौर में और आगे भागीदारी करने से हटा लिया। यह माना जा सकता है कि यह निर्णय टीआईएमएसएस और पीआईआरएलएस जैसे बड़े, अधिक व्यापक भागीदारी वाले, और अधिक प्रभावशाली मूल्यांकनों से निकले उन परिणामों से प्रेरित हुआ हो जिनमें एशिया और यूरोप के अनेक देशों को पढ़ने, गणित और विज्ञान में अमेरिका से आगे निकलता हुआ पाया गया।

संक्षेप में, पूरी दुनिया की तस्वीर कुछ ऐसी है जिसमें सामाजिक विज्ञान ''अधिक ठोस'' विषयों से महत्व की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। अभी समझदारी इसी में प्रतीत होती है कि यदि कोई देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्पर्धा करना चाहता है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को अपने कामगारों को संख्याओं और शब्दों को समझने के लिए तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करना जरूरी है। आज जब देश निरन्तर कम पड़ती जा रही वैश्विक सम्पदा में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए होड़ कर रहे हैं, तब ऐसे सक्रिय नागरिकों, जिन्हें इतिहास, संस्कृति और मानवीय व्यवहार की बारीक समझ हो, को तैयार करने की बात काफी हद तक एक पीछे से आने वाला विचार भर बनकर रह गया है।

संक्षेप में, पूरी दुनिया की तस्वीर कुछ ऐसी है जिसमें सामाजिक विज्ञान ''अधिक ठोस'' विषयों से महत्व की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। अभी समझदारी इसी में प्रतीत होती है कि यदि कोई देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्पर्धा करना चाहता है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को अपने कामगारों को संख्याओं और शब्दों को समझने के लिए तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करना जरूरी है।

पर इतिहास, समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में शिक्षा को त्यागकर बहुत दूर चला जाने वाला कोई भी देश अपना भारी नुकसान करता है। बेशक सक्षम, योग्य, कामगार आबादी को तैयार करने के लिए उपयुक्त शिक्षा के महत्व से शायद ही कोई इन्कार करेगा, और इसी कारण से साक्षरता और संख्या ज्ञान पाठ्यचर्या में होते हैं, और उनका होना जरूरी भी है। लेकिन,

मानवीय पूँजी–निर्माण ही राज्यों के शिक्षा में निवेश का एकमात्र कारण नहीं होता। स्कूल ऐसे स्थान हैं जहाँ युवा लोग नागरिकता, और सार्वजनिक कार्यों के तरीके सीखते हैं, जहाँ उनके सामाजिक और राजनैतिक लगाव निर्मित होते हैं, जहाँ किसी समाज के भीतर विद्यमान भेदों को प्रतिबिम्बित किया जा सकता है या रूपान्तरित किया जा सकता है। इन कारणों से, पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञानों का भी स्थान – कुछ लोग कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान – होता है, और इसका आगे भी बना रहना जरूरी है।

आर्थिक दबावों, जो एक समर्थ कामगार आबादी की माँग करते हैं, और सामाजिक अपेक्षाओं, जो एक सक्रिय नागरिक समुदाय की माँग करती हैं, के बीच स्वाभाविक खींचतान संसार के किसी एक भाग तक सीमित नहीं है। इसे सम्पन्न देशों में और गरीब देशों में, लम्बे समय से स्थापित लोकतन्त्रों में और नए–नए लोकतन्त्रों में, सभी जगह देखा जा सकता है। हालाँकि सारे संसार में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विषय पर ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं, पर मैं यहाँ अपनी पड़ताल को थोड़े से देशों तक ही सीमित रखूँगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पाठ्यचर्या और शिक्षण पद्धतियों में इतनी विविधता है कि उनमें से अधिकांश को यहाँ अनछुआ छोड़ना अफसोस की बात है। पर मुझे आशा है कि यह लेख पाठकों की रुचि को उकसाएगा और वे इस बारे में और अधिक जानने की पहल करेंगे।

'अच्छे' के लिए या 'बुरे' के लिए

सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वैश्विक तस्वीर में प्रवेश करने से पहले, हमें शिक्षाकर्मियों की तरह, अपने को यह याद दिलाना उपयोगी होगा कि शिक्षा निसंदिग्ध रूप से हमेशा अच्छी ही होती हो ऐसा नहीं है। अक्सर और अनेक जगहों पर किसी खास विचारधारा को मन में बैठाने के लिए और राज्यशक्ति को मजबूत करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण को विकृत करके उपकरण की तरह उपयोग किया जाता है। ऐसे सुरक्षित शरणस्थल होने के बजाय, जहाँ विद्यार्थी समाज के सामने खड़ी समस्याओं के बारे में समीक्षात्मक ढंग से सोचना सीखें, स्कूल स्वयं ही ऐसे संघर्ष–क्षेत्र बन जाते हैं जहाँ समुदायों के बीच वैचारिक युद्ध लड़े जाते हैं। शासक वर्ग अपनी पसन्द के जातीय, धार्मिक या भाषाई समूह को उपकृत करने के लिए इतिहास को तोड़ते–मड़ोरते, विकृत करते और यहाँ तक कि गढ़ भी लेते हैं। स्कूलों का ऐसा दुरुपयोग जहाँ हिंसक संघर्षों से पीड़ित क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित है, वहीं इसे अधिक स्थायित्व वाले देशों में भी देखा जा सकता है। अमेरिका के टैक्सास राज्य में सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या के ऊपर हुआ ताजा विवाद इसका सबूत है। इसमें राज्य शिक्षा मण्डल (स्टेट बोर्ड ऑफ ऐजुकेशन) के दक्षिणपन्थी सदस्यों का एक समूह ईसाई धर्म और अनुदारवादी राजनैतिक आन्दोलनों और नेताओं पर जोर देने के लिए अमरीकी इतिहास की पुस्तकों में संशोधन करवाने में सफल हुआ।

यह मानते हुए, कि सभी लोगों को ऐसी शिक्षा पाने का अधिकार है जो, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूनीवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइटस) के शब्दों में, ''सभी राष्ट्रों, नस्लीय और धार्मिक समूहों में आपसी समझ, सहिष्णुता और मित्रता को बढ़ावा देती है,... और...शान्ति को बनाए रखने में सहायक होती है'', हममें से उन लोगों को जो शिक्षा क्षेत्र में हैं, हमारे अपने देशों में और विदेशों में, स्कूलों में सामाजिक विज्ञानों के उचित स्थान के लिए लड़ना आवश्यक है। यदि हम शान्ति, सुरक्षा और सभी लोगों की सामान्य गरिमा के आदर्शों को मानते हैं तो यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों, चाहे वे जैसे भी हालातों में रहते हों, को सोचने, कार्य करने, और बराबरी के साथ भागीदारी करने के औजार दिए जाएँ, यह हमारी जिम्मेदारी है।

वैश्विक परिदृश्य

हाल ही में प्रकाशित वर्ल्ड सोशल साइंस रिपोर्ट 2010, जो यूनेस्को तथा इन्टरनेशनल सोशल साइंस काउंसिल का साझा प्रयास है, इस बात की ओर ध्यान दिलाती है कि सामाजिक विज्ञान पर होने वाला संवाद ज्यादातर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप द्वारा संचालित किया गया है। यह शायद आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि संसार के सबसे पुराने लोकतंत्र इन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं, और सार्वजनिक स्कूल की संस्था को जैसा आधुनिक युग में समझा जाता है, ये क्षेत्र उसके जन्मस्थान हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक स्कूलों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत बनाने के महत्वपूर्ण साधनों की तरह देखा जाता है। अधिकतर देशों के विपरीत, यूएस (संयुक्त राज्य अमेरिका) में विकेन्द्रीकृत शिक्षा व्यवस्था है। वहाँ वैसे तो एक संघीय शिक्षा विभाग है, पर काफी हद तक स्कूलों का नियोजन, संचालन और वित्तीय आबंटन राज्य के और स्थानीय स्तर पर किया जाता है। शिक्षा पर होने वाले व्यय का लगभग 83% राज्यों और स्थानीय सरकारों से आता है, और शिक्षा के मापदण्ड तय करने और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं स्तरों पर निहित रहती है। इस विकेन्द्रीकरण के बावजूद, सभी राज्यों के पाठ्यक्रमों में कुछ समानताएँ हैं, और उनमें से एक यह है कि सभी विद्यार्थियों को देश के इतिहास और सरकार के बारे में पढ़ना आवश्यक है। यह अमेरिका के संस्थापकों के दृष्टिकोण की उपज है जो मानते थे कि यदि किसी भी लोकतंत्र के नागरिक सुशिक्षित न हों तो वह बचा नहीं रह सकता। संयुक्त राज्य के दूसरे

राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने लिखा था, ''लोगों में सामान्य ज्ञान के बिना स्वतंत्रता को बचाए नहीं रखा जा सकता।''

इसलिए सामाजिक शिक्षा के पैरोकार आई.ई.ए. के नागरिक शिक्षा अध्ययन में आगे भाग न लेने के सरकार के निर्णय से हतोत्हासित हैं, क्योंकि इससे यह निराशाजनक सन्देश जाता है कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के ज्ञान को नापना बेकार है।

यूएस में सार्वजनिक स्कूली शिक्षा का तेजी से विकास सही तौर पर हॉरेस मान के नेतृत्व में 1830 के दशक में शुरू हुआ। वे स्कूलों के माध्यम से लोकतांत्रिक नागरिकों को ढालने के संस्थापकों के आदर्शों को मानते थे। इस दृष्टि के अनुसार ही यूएस में सामाजिक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य युवाओं को अपनी सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में बुनियादी जानकारी, व्यक्ति पर जोर देने वाले अधिकारों की समझ, और जो संस्थाएँ व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अतिआवश्यक हैं उनमें आधारभूत भरोसा प्रदान करना था, और अभी भी है। जैसा ऐलिनॉर रूजवेल्ट ने कहा था, ''हमारे बच्चों को उनकी सरकार के सामान्य ढाँचों को जानना चाहिए, और फिर उन्हें यह जानना चाहिए कि वे कहाँ सरकार के सम्पर्क में आते हैं, कहाँ वह उनके दैनिक जीवन को छूती है और कहाँ सरकार पर उनका प्रभाव पड़ता है। यह उनके लिए दूर की बात, या किसी और का सरोकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको यह समझना जरूरी है कि कैसे लोकतंत्र के पहिए का हर दाँता महत्वपूर्ण है और पूरी मशीन के सुचारु रूप से चलने के लिए जिम्मेदार है।''

सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परम्परा और प्रगति के बीच में यही तनाव संसार के अपेक्षाकृत नए लोकतंत्रों जैसे अफ्रीका और भूतपूर्व सोवियत खेमे के देशों में दिखाई देता है। यूएस और पश्चिमी यूरोप की तुलना में इन देशों की प्रवृत्ति सामाजिक रूप से अधिक रूढ़िवादी होती है और उनमें आलोचनात्मक सोच और व्यक्तिगत सक्रियता पर जोर देने की उतनी सम्भावना नहीं होती।

हालाँकि, सामाजिक विज्ञान शिक्षा अमेरिकी स्कूलों का एक केन्द्रीय अंग है, और हमेशा रहा है, परन्तु अधिकांश अमेरिकी लोग निम्न स्तर का राजनैतिक ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। इसलिए सामाजिक शिक्षा के पैरोकार आई.ई.ए. के नागरिक शिक्षा अध्ययन में आगे भाग न लेने के सरकार के निर्णय से हतोत्हासित हैं, क्योंकि इससे यह निराशाजनक सन्देश जाता है कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के ज्ञान को नापना बेकार है। इन विषयों का स्थान सुरक्षित करने के संघर्ष के अलावा, यूएस में सामाजिक विज्ञान समुदाय कई बार इस बात को लेकर, कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, आपस की लड़ाइयों में उलझ जाता है। इस जटिल वाद विवाद के अतिसरलीकरण का जोखिम उठाते हुए, इस मुद्दे को ''बहुसंस्कृतिवादी'' की तरह निरूपित किया जा सकता है। जैसे जो ऐसी पाठ्यचर्या देखना चाहते हैं जिसकी प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय हो और जो अल्पसंख्यकों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदानों को रेखांकित करता हो – बनाम ''परम्परावादी''. जो प्रेरक चरित्रों (उदाहरण के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन) और देशभक्तिपूर्ण आख्यान पर ध्यान दिए जाने के पक्षधर हैं। शिक्षा व्यवस्था के विकेन्द्रित स्वरूप के कारण, अपेक्षाकृत उदार जिलों के अमेरिकी विद्यार्थी प्रायः ऐसी सामाजिक शिक्षा पाते हैं जिसकी प्रकृति अधिक अन्तर्राष्ट्रीय होती है, जबकि अनुदार जिलों के विद्यार्थी अधिक परम्परावादी चश्मे से देखना सीखते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में भी विकेन्द्रित व्यवस्था है जिसमें स्कूलों के लिए मुख्य रूप से राज्य और क्षेत्र जिम्मेदार हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण द्वारा प्रदान की गई नागरिक क्षमताओं की ऑस्ट्रेलियाई विद्यार्थियों की उपलब्धि भी अमेरिका की तरह ही प्रभावहीन है। आईईए के नागरिक शिक्षा अध्ययन पर ऑस्ट्रेलिया सरकार की रिपोर्ट कहती है कि ''केवल आधे ऑस्ट्रेलियाई विद्यार्थियों को ही सुचारु ढंग से काम करने वाले लोकतंत्र के लिए अनिवार्य पूर्व शर्तों की समझ होती है। उन्हें इसकी गहरी समझ नहीं है कि उनके नागरिक अधिकारों में क्या निहित है...न ही उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर आर्थिक मुद्दों के प्रभाव की गहरी समझ है।'' इसे सुधारने की जरूरत के अलावा ऑस्ट्रेलिया के सामने उसकी मूल आबादी में व्याप्त गरीबी और असमान अवसरों के दुस्साध्य मुद्दे भी हैं। सरकार पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि समस्या के समाधान के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में यूरोप–केन्द्रित पक्षपात को दूर करने के लिए वह समुचित कार्यवाही नहीं करती। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के एक नए मसौदे पर अभी परामर्श चल रहा है, और यदि वह सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकों के दोषों को दूर करने में सफल होता है तो वह अन्य देशों को भी उनके वंचित समूहों को ताकतवर बनाने के लिए एक प्रारूप प्रदान कर सकता है।

भूमण्डल की दूसरी तरफ, पश्चिमी यूरोप में, शिक्षा सामान्यतया

केन्द्रीकृत मामला है। एक पुराना चुटकुला है कि फ्रान्स के शिक्षामंत्री किसी भी दिन अपनी घड़ी देखकर आपको एकदम ठीक–ठीक बता सकते हैं कि उस समय सारे फ्रान्स में कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है। वाकई, फ्रान्स में सामाजिक विज्ञान शिक्षा का एक विशेष लक्षण केन्द्रीय राज्य के प्रति सम्मान की भावना और एक अखण्ड फ्रान्सीसी पहचान को बढ़ावा देने में एक समान होना रहा है। पर, फ्रान्स और यूके, जर्मनी, नीदरलैण्ड और स्कैन्डीनेवियाई देशों सहित उसके पड़ोसी, उस महाद्वीप में हो रहे दो प्रमुख परिवर्तनों के द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षा की भूमिका को मिल रही चुनौती का सामना कर रहे हैं। पहली है, अफ्रीका और मध्यपूर्व से हो रहे आप्रवासन की लहर, जिसने इन लोकतंत्रों को ठिठककर यह सोचने पर, कि वे सचमुच में कितने सहिष्णु और समतावादी हैं, और फ्रेंच, डैनिश, जर्मन आदि होने का मतलब क्या है, इसकी सम्भावित अधिक व्यापक धारणा बनाने पर मजबूर किया है। दूसरा परिवर्तन यूरोपीय यूनियन की स्थापना और उसका विकास है। जिसकी माँग है कि पाठ्यचर्या एक विशेष राष्ट्रीय आख्यान का बोध कराने और ईयू के सदस्यों की परस्पर राजनैतिक और आर्थिक निर्भरता की समझ को बढ़ावा देने के बीच सन्तुलन बनाए। यूरोप की राष्ट्रीय सरकारों को इस चुनौती का सामना बहुत सम्भलकर करने की जरूरत है। क्योंकि एक तरफ संघ के लाभ हैं तो दूसरी ओर अनेक मतदाताओं के मन में ईयू के प्रति गहरा संशय है। कुछ दृष्टियों से, यह यूएस में बहुसंस्कृतिवादियों और परम्परावादियों के बीच चलने वाली रस्साकशी से भिन्न नहीं है। सामाजिक विज्ञान के विषय नागरिकों की राजनैतिक और राष्ट्रीय पहचान बनाने में ऐसे तरीकों से प्रमुख भूमिका निभाते हैं इसलिए वे हमेशा, समाज कैसा दिखना चाहिए और उसे कैसे काम करना चाहिए, इसकी दो (या अधिक) कल्पनाओं के बीच फंसे हुए प्रतीत होते हैं।

सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में परम्परा और प्रगति के बीच में यही तनाव संसार के अपेक्षाकृत नए लोकतंत्रों जैसे अफ्रीका और भूतपूर्व सोवियत खेमे के देशों में दिखाई देता है। यूएस और पश्चिमी यूरोप की तुलना में इन देशों की प्रवृत्ति सामाजिक रूप से अधिक रूढ़िवादी होती है और उनमें आलोचनात्मक सोच और व्यक्तिगत सक्रियता पर जोर देने की उतनी सम्भावना नहीं होती। फिर भी, वे यह जानते हैं कि उन्हें, वर्ल्ड सोशल साइंस रिपोर्ट 2010 के शब्दों में ''मानवता के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों, जैसे कि गरीबी, महामारी और जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए सामाजिक विज्ञानों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है''। विडम्बना यह है कि अफ्रीका के अधिकांश उप–सहारा क्षेत्र की शिक्षा के द्वारा नागरिक क्षमताएँ विकसित करने की असमर्थता उत्तरी भभूमण्डल के द्वारा थोपे गए ढाँचागत सुधारों, जो गरीब देशों को शिक्षा पर व्यय में कटौती करने पर मजबूर करते हैं, के कारण और बढ़ जाती है। यदि ये लोकतंत्र अपने विद्यार्थियों को नागरिकता की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने में असमर्थ रहते हैं तो धनी देशों द्वारा नए लोकतंत्रों की मदद करने की व्यक्त की गई इच्छा के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं दिखती।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक विज्ञान शिक्षा के असर के बारे में हुए शोधों के परिणामों से संकेत मिलता है कि सहभागिता वाली विद्यार्थी–केन्द्रित शिक्षा पद्धति ही नागरिक अवधारणाएँ सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऐसी शिक्षण पद्धति उत्तरी भूमण्डल में अधिक प्रचलित है, बजाय दक्षिणी भूमण्डल के जहाँ शिक्षक–केन्द्रित रटकर सीखने की अपेक्षाकृत अधिक पारम्परिक पद्धति आम है। इन चुनौतियों के बावजूद, अफ्रीका के कुछ देश सामाजिक विज्ञान शिक्षा में बड़े कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, रवांडा का शिक्षा मंत्रालय इस बात को जरूरी मानने से नहीं हिचकिचाया कि विद्यार्थी, टुटू और टुटसी जनजातियों के बीच हुई हिंसा में संचार माध्यमों की भूमिका सहित, 1994 के नरसंहार के बारे में जानें। दक्षिण अफ्रीका में, जो अभी भी रंगभेद के घावों को भरने की मशक्कत कर रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या विभिन्न विषयक्षेत्रों में ''गरीबी, असमानता, नस्ल, लिंग, उम्र, विकलांगता, और ऐसी चुनौतियों जैसे कि एचआईवी/एडज के प्रति संवेदनशील होने'' का प्रयास करती है। अतीत के दैत्यों का सामना करना आसान काम नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को उनके इतिहास के बारे में सच बताकर ही कोई देश शान्तिपूर्ण भविष्य का निर्माण करने की आशा कर सकता है।

इराक एक ऐसा देश है जो अपने हाल के अतीत को समझने, उससे निपटने, और उसे स्कूलों में कैसे पेश किया जाए, यह सोचने के दौर से गुजर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक हाल का लेख ''इन रिराइटिंग हिस्ट्री, इराक ट्रैड कॉशसली'' संघर्ष के बीच में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को पूरी तरह दुरुस्त करने की कठिनाई पर प्रकाश डालता है। इस बात पर ध्यान दिलाते हुए, कि सद्दाम हुसैन के हटाए जाने तक इराक में इतिहास की शिक्षा ''बाथ पार्टी के तौर–तरीकों को मन में बैठाने का और जनाब हुसैन के महिमामण्डन को बढ़ावा देने का औजार'' थी, यह लेख दर्शाता है कि उसकी मृत्यु के बाद देश के विभिन्न सम्प्रदायों में कोई सहमति नहीं बन पाई है कि किसके दृष्टिकोण से देखा गया इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए।

यहाँ फिर यह खींचतान, कि सामाजिक विज्ञान के मापदण्ड परिभाषित करने का हक किसे है, संसार के अन्य भागों में, बहुसंस्कृतिवादियों और परम्परावादियों के बीच, यूरोप पर जोर देने वाले ईयू समर्थकों और ईयू के प्रति संशयवादियों के बीच, और

सहभागितापूर्ण शिक्षण पद्धति और रटकर सीखने के बीच चल रहे संघर्ष को प्रतिध्वनित करती है। जहाँ इन भिन्न दृष्टिकोणों के बीच अलंघ्य प्रतीत होने वाली खाई को देखते हुए हताश हो जाना आसान है, वहीं इस मतभेद में एक शैक्षिक अवसर को खोजना भी सम्भव है, और शिक्षकों की हैसियत से वही करना हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि वर्ल्ड सोशल साइंस रिपोर्ट 2010 हमें याद दिलाती है, ''मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार से यह समझने में कि संसार कैसे काम करता है,'' सामाजिक विज्ञान हमारी मदद करता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो, इसकी बहस अपने आप में अगली पीढ़ी के नागरिकों के लिए एक सबक है; यदि हम अपने मतभेदों पर सौजन्यतापूर्वक और एक साझा उद्देश्य की भावना से चर्चा कर सकें, तो हम उन्हें दिखा पाएँगे कि जिम्मेदार होने और वैश्विक समुदाय के सक्रिय सदस्य होने का क्या मतलब है। वाकई, हमारी सबसे गम्भीर साझा चुनौतियों – गरीबी से लेकर युद्ध और जलवायु परिवर्तन तक – का समाधान खोजना इस पर निर्भर करता है कि हम कितने कारगर ढंग से आज सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं।

ऐन हॉर्विटज़ *ने अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी मास्टर की डिग्री हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वे पेरिस में यूनैस्को के सैक्शन फॉर ऐजुकेशन इन पोस्ट कॉनफ्लिक्ट एण्ड पोस्ट डिजॉस्टर सिचुएशन्स में परामर्शदाता हैं। उनसे इस ann.horwitz@gmail.com ईमेल पते पर सम्पर्क किया जा सकता है ।*